

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
शहरी विकास विभाग,  
उत्तरांचल, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग:

देहरादून:

दिनांक-27 फरवरी, 2006

**विषय :** नगर पंचायत, सुल्तानपुर जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों की वर्ष 2005-06 में प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पंचायत, सुल्तानपुर जनपद उधमसिंह नगर में प्रस्तावित कार्यों हेतु ₹0122.19 लाख की लागत के आगणन के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत ₹0112.65 लाख (रुपये एक करोड़ बारह लाख पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- 2- अवस्थापना विकास मद से स्वीकृत की जा रही धनराशि को स्थानीय निकायों के द्वारा अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी का संयुक्त रूप से एक पृथक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोल कर जमा किया जायेगा, किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों में न किया जाय, इसके लिए सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- 3- उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययवर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।
- 4- स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- 5- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की

*सामा*

जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंसी के अभियंता/अधिशाली अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

- 6- स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल, मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित किये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
- 7- निर्माण एजेंसी के चयन में शासनादेश संख्या 452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- 8- उक्त कार्य/मार्ग यदि नगर पालिका के क्षेत्र में ही हैं तब उक्त कार्य हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, अन्यथा शासन को वस्तुस्थिति से सूचित कर धनराशि 31-3-2006 तक समर्पित कर दी जायेगी।
- 9- यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं तब सम्बन्धित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को दिनांक 31-03-06 तक समर्पित कर दी जायेगी।
- 10- कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात् योजना की लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय, पूर्ण करने का समय तथा वित्त पोषण के स्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना की लागत से ही लगाया जायेगा।
- 11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथा आवश्यकता ही किश्तों में आहरण किया जायेगा।
- 12- सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किश्त तब ही निर्गत की जाये जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।
- 13- आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशाली अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- 14- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- 15- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- 16- विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो0नि0वि0 के अधिशाली अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों से करा लिया जायेगा एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।



- निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
- 18— कार्य पूर्ण होने पर इसे वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
- 19— कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- 20— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2005-06 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-13, लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 21— यह आदेश वित्त विभाग के अशा०प०सं०-167/XXVII(2)/2006, दिनांक-22 फरवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अमरेन्द्र सिन्हा)  
सचिव।

सं० 38०५/V-श०वि०-06, तददिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
- 2— निजी सचिव, मा० नगर विकास मंत्री जी।
- 3— वरिष्ठ क्रोषाधिकारी, देहरादून।
- 4— जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
- 5— वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
- 6— निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।
- 7— अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सुल्तानपुर।
- 8— बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महाश्री बकरियाल)  
अनुसंधान  
शहरी विकास  
उत्तरांचल शासन

(एल० फैनई)  
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या 380 / V-शा0वि0-06 / 197(सा0) / 2005 दिनांक 27 फरवरी, 2006 का  
संलग्नक-

(लाख रुपये)

क्र०सं०	कार्यका नाम	आगणन की लागत	अनुमोदित आगणन / स्वीकृतधनराशि
01	वार्ड नं०-1,2,3,4,5 (एस०सी० कालोनी) में सी०सी० रोड का निर्माण	74.32	69.58
02	वार्ड नं०-4 में नाले का निर्माण	19.60	19.15
03	मौ०शिवनगर में अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए मैरिज हॉल का निर्माण	7.81	6.30
04	राष्ट्रीय राजमार्ग के बाँयी ओर दुकान का निर्माण	9.27	7.35
05	राष्ट्रीय राजमार्ग के दाहिनी ओर दुकानों का निर्माण	11.19	10.27
	कुल आगणन लागत-	122.19	112.65

(रुपये एक करोड़ बारह लाख पैंसठ हजार मात्र)

प्रमाणित  
(अध्यापिका ठकुरियास)  
अनुसूचित  
राष्ट्रीय विभाग  
उत्तराखण्ड शासन